को नीचे दर्शाया गया है:—

खण्डों के नाम	(लाखों रुपये में) केन्द्रीय रिलीज	
	1994-95	1995-96
बिस्फी	12.00	30.00
पंडौल	12.00	30.00
बासुपट्टी	12.00	30.00
राजनगर	12.00	30.00
अन्धराठड़ी	12.00	30.00
लखनौर	12.00	30.00
बाबूबरही	30.00	30.00
बेनीपट्टी	30.00	40.00
मधुबनी	30.00	30.00
फलपरास	30.00	30.00
कुल	192.00	310.00

Encouragement of NRI Entrepreneurs for Power Generation

566. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether NTPC is actively encouraging NRI entrepreneures to develop and participate in power generation in the country;

(b) if so, the details of such steps taken by NTPC;

(c) whether any financial participation has been undertaken by NTPC in NRI proposals for power plants;

(d) if so, the details of such participation proposed, approved or considered on a plnat-by-plant basis; and

(e) the steps proposed to be taken to ensure that NTPC participates in all the foreign power-generation proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) National Thermal Power Corporation (NTPC) has entered into a Promoters agreement with Spectrum Technologies, USA, Inc., Non Resident Indian (NRI) entity, and Jaya Food Industries, Hyderabad, on 29.6.93 to set up a 208 MW gas power project at Kakinada, Andhra Pradesh. In terms of the pattern of shareholding incorporated in the Promoters Agreement, 10% of the initial issued and paid up equity share capital of the joint venture company shall be subscribed and held by NTPC.

(e) While the present policy of Government of India does not preclude NTPC or any Corporation from going into a joint venture with any private company (whether Indian or foreign including NRI), the Government is not contemplating taking any steps for ensuring that NTPC participates in all foreign power generation proposals.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को आबंटित भूमि का सर्वेक्षण

567. श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को आबंटित की गई भूमि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या आवश्यक कार्रवाई की जा रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आबंटित भूमि के संबंध में अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।